

v/; k; &4

NRrhl x<+ dh vFkD; oLFk & , d fl gkoykdu

4.1.0 भूमिका :

4.1.1 चूँकि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था एवं विभिन्न क्षेत्रों/स्वरूपों में उसका विकास ही राज्य सरकार को राज्य के **l kelftd , oa vkfFkd fodkl** के लिये वित्तीय साधन सृजित एवं एकत्रित करने का आर्थिक आधार उपलब्ध कराती है, अतः यह आवश्यक हो जाता है, कि राज्य की अर्थव्यवस्था की विभिन्न दिशाओं में हुई प्रगति तथा साथ ही राज्य के विकास एवं परिवर्तन मार्ग की प्रमुख बाधाओं की त्वरित समीक्षा की जाय। इसीलिये रा.वि.आ. से अपेक्षा की जाती है, कि वह राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को वित्तीय अंतरण के पैकेज की अनुशंसा विभिन्न क्षेत्रों में राज्य अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों एवं संवृद्धि की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में करे। इस समीक्षा से राज्य के विकास के लिये आवश्यक प्राथमिकतायें भी स्पष्ट होंगी।

4.1.2 **orëku NRrhl x<+ jkT; dk xBu 1 uoEcj 2000 dkj e/; ins'k dks folkkftr dj fd;k x;k** था। इस भू-भाग का इतिहास उतार-चढ़ावों से भरा हुआ रहा है। पहले यह विभिन्न राज्यों का भाग बनता रहा तथा अंततः एक पृथक राज्य के रूप में उसे अपनी सांस्कृतिक एवं जातिगत पहचान प्राप्त हुई। नये राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1 नवम्बर 1956 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, **e/; ins'k** में समाहित किया गया था तथा पूरे 44 वर्षों तक उसी राज्य का भाग रहा। 1 नवम्बर 1956 को नये राज्य, **e/; ins'k** का एक भाग बनने से पूर्व यह भू-भाग पूर्व **e/; ins'k** राज्य का अंग था, जिसकी राजधानी **ukxij** थी। उससे भी पहले **fcfV'k 'kkl u** के अंतर्गत यह **l d'y ikfol l , oa cjkj jkT; ¼ hih, oa cjkj½** का अंग था। **NRrhl x<+ jkT;** के कुछ क्षेत्र **fcfV'k 'kkl u** के समय शासक राज्य थे, परन्तु बाद में उनका विलय **e/; ins'k** में कर

दिया गया। इस प्रकार हम पाते हैं, कि प्रक्षेत्र की विकास प्रक्रिया की निरंतरता में क्षेत्र का बार-बार एक राज्य से दूसरे में हस्तांतरण बाधा बना रहा। अब आशा की जा सकती है, कि नया **NRrh x<+jkt**; जो आकार में भले ही छोटा हो, परन्तु जहाँ विकास की असीम संभावनायें हैं, अब राज्य के लोगों की आंकाक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न दिशाओं में तीव्र प्रगति करेगा।

4.1.3 राज्य को अविभाजित **e/; ins'k** का प्रशासकीय, वित्तीय, विधिक एवं संस्थागत ढाँचा विरासत में प्राप्त हुआ है, परन्तु अब उसे उसमें अपनी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनज़र बदलाव करने का अवसर है। राज्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान समीक्षा, **NRrh x<+jkt**; से संबंधित अत्यल्प समकों और वह भी राज्य के निर्माण के बाद के केवल चार या पाँच वर्षों की अल्पावधि पर आधारित है। नये राज्य के लिये उचित समंक आधार निर्मित करने में अधिक देरी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भविष्य के विकास कार्यक्रम आवश्यक रूप से उसी पर आधारित होंगे।

4.2.0 छत्तीसगढ़ एक कम विकसित राज्य :

4.2.1 वर्तमान में राज्य विकास की महती संभावनाओं के साथ-साथ अर्धविकास एवं व्यापक गरीबी का दृश्य उपस्थित करता है। राज्य की गिनती देश के कम विकसित राज्यों में की जाती है। भूमि, वन एवं खनिज साधनों की उसकी व्यापक संभावनायें अर्धदोहित रही हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य में बार-बार हस्तांतरण तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की नीतियों एवं संस्थागत संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न अनेक अन्य कारक प्रभावशील रहे हैं, जिन्हें हम इस अध्याय में चिन्हित करेंगे। वर्ष 1956 में **e/; ins'k** जैसे कम विकसित राज्य का अंग बन जाने के कारण, यह प्रक्षेत्र **e/; ins'k** जैसे बड़े राज्य के सम्मुख उपस्थित विभिन्न अवरोधों एवं रुकावटों के चलते अपने अर्धविकास को दूर नहीं कर सका।

4.2.2 अपने चारों ओर छः राज्यों यथा *e/; ins'k mRrjins'k] >kj [k.M] mMhl k] egkjk"V^a, oa vkkai ns'k* से घिरा हुआ, यह एक भूमि-आबद्ध (Land -locked) राज्य है। इसकी व्यापक गरीबी एवं अर्धविकास का आंशिक कारण है, यहाँ की जनसंख्या के एक बड़े भाग (43.37%) में अनुसूचित जाति (11.61%) एवं अनुसूचित जनजाति (31.76%) का होना, जबकि यह अनुपात पुनर्गठित *e/; ins'k* के लिये 35.40% तथा संपूर्ण देश के लिये 24.60% है। यही तथ्य राज्य की एक प्रमुख प्राथमिकता को रेखांकित करता है, कि उसके विकास कार्यक्रमों को इन पिछड़े वर्गों के उत्थान की ओर मोड़ना होगा। इनकी अवहेलना गरीबी एवं अर्धविकास को चिर स्थायी बना देगी।

4.3.0 जनांकिकीय परिदृश्य :

4.3.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, *NRrhl x<+jkt; dh dy tul [;k* 2.08 करोड़ है, जो पुनर्गठित *e/; ins'k jkt;]* जिसकी जनसंख्या 603 करोड़ है, के एक तिहाई से कुछ अधिक है। राज्य का *dy Hk&kyd {k=Qy* 137 हजार वर्ग कि.मी. आँका गया है, जबकि *e/; ins'k* का यह क्षेत्रफल 308 हजार वर्ग कि.मी. है। नये राज्य का क्षेत्रफल अविभाजित *e/; ins'k jkt;* के क्षेत्रफल का 44.48% है, जबकि उसकी जनसंख्या 34.49% है। विरासत में अधिक क्षेत्रफल एवं कम जनसंख्या मिलने के कारण नये राज्य *NRrhl x<* का जनसंख्या घनत्व, वर्ष 2001 में 154 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था, जबकि यह *e/; ins'k* में 196 तथा *l á wkZ Hkjr* में 324 था। इस तथ्य की वजह से ही राज्य में प्रशासन की इकाई लागत बढ़ जाती है और साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं का प्रदाय मंहगा हो जाता है।

4.3.2 राज्य जहाँ की कुल जनसंख्या का 80% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, प्रमुख रूप से ग्रामीण हैं। यह अपेक्षाकृत कम नगरीकृत राज्यों में से एक है तथा यहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 20% है, जबकि यह *e/; ins'k* में 26% एवं *l á wkZ Hkjr* में लगभग 30% है। राज्य की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर निर्भर है, जो लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है। इस समीक्षा से उभरने वाला एक

अन्य तथ्य यह है, कि विकास कार्यक्रमों का अत्यधिक झुकाव ग्रामीण विकास की ओर होना आवश्यक है।

4.3.3 वर्ष 1991–2001 के दशक में राज्य में जनसंख्या वृद्धि 18.06% थी, जबकि यह *e/; ins'k* में 24.34% एवं *l á w k z H k j r* में 21.34% थी। जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1.66% थी, जो *l e x z H k j r* की दर 1.93% से काफी कम थी। वर्ष 2001 की जनगणना में, पिछले दशक की तुलना में, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की गयी है। राज्य में लिंग अनुपात में कुछ सीमांत सुधार, 1990–91 में 985 से 2001 में 990 दर्ज किया गया है। यह अनुपात *e/; ins'k* एवं *H k j r h ; v k s r j* जो वर्ष 2001 में क्रमशः 920 एवं 933 था, से काफी ऊँचा है। *N R r h l x <* की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अनुपात में कमी हुई है— वर्ष 1991 के 19.94% से वर्ष 2001 में 16.68% रह गया। इसकी तुलना में *e/; ins'k* एवं *H k j r* का वर्ष 2001 का यह अनुपात क्रमशः 17.58% एवं 15.42% था। राज्य जनसंख्या की कम दशकीय वृद्धि दर एवं उच्च शिशु मृत्यु दर इसके कारण हो सकते हैं। *l á w k z H k j r* की 68 प्रति हजार की तुलना में राज्य की शिशु मृत्यु दर 79 है।

4.4.0 सामाजिक अधो-रसंरचना – मानवीय संसाधन विकास :

4.4.1 राज्य में अनेक क्षेत्रों जैसे साक्षरता दर, पोषण स्तर, पेयजल आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवायें तथा महिलाओं, बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्गों के विकास, में काफी पिछड़ापन है। मानवीय संसाधन विकास के अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक कमियाँ हैं, जिनकी न्यूनतम संभावित समयावधि में पूर्ति की जाना आवश्यक है।

4.4.2 वर्ष 1991 में *N R r h l x <* की *l k { k j r k n j* 42.90% थी (पुरुष साक्षरता दर 58.10% एवं महिला 27.50%) , जो *H k j r h ; v k s r*— 52.20% (पुरुष 64.10% एवं महिलायें 39.20%) से काफी कम है। वर्ष 1991 में *e/; ins'k* की दर *N R r h l x <* से कुछ अधिक थी— पुरुष *l k { k j r k n j* 58.50%, महिला दर 29.40% तथा औसत *l k { k j r k n j* 44.70%। वर्ष 2001 में *e/; ins'k* की तुलना में औसत *l k { k j r k n j*

एवं महिला *I k{kjrk nj* के मामलों में *NRrhl x<* ने अपनी तुलनात्मक स्थिति में सुधार किया है। *I kj.kh da 4-1* में *e/; ins'k ,oa Hkjr dh rgyuk ea NRrhl x<+dh I k{kjrk njka dks inf'kr fd; k x; k g*

4.4.3 *I k{kjrk* के क्षेत्र में *e/; ins'k* एवं *NRrhl x<* दोनों राज्यों में हुई तीव्र प्रगति का श्रेय, *jkttho xkakh f'k{k fe'ku* के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना द्वारा किये गये प्रयासों को दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार के इस कार्यक्रम ने न केवल देश के अंदर वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है।

4.4.4 अविभाजित राज्य की सरकार ने 20 अगस्त, 1994 को शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के चुने हुये क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से राज्य में सात राजीव गाँधी मिशनों का गठन किया था। अनुभव-जन्य जन आवश्यकताओं के विकेंद्रित समाधान के लिये *iajk-l & Fkk;s* आवश्यक संस्थागत संरचना उपलब्ध करा रही हैं। प्रयास निरंतर जारी हैं। मानव विकास रिपोर्ट में चिन्हित ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जहाँ विकास धीमा है, गरीबी एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा स्कूली छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब यह सर्वज्ञात है, कि 1990 के दशक की अधिक तीव्र वृद्धि के लाभ सभी प्रक्षेत्रों एवं सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों को समान रूप से नहीं मिल सके हैं।

4.4.5 *tu LokLF;* एक ऐसा क्षेत्र हैं, जिसमें बड़ी कमियाँ है, परंतु प्रगति धीमा है। राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। यहाँ 16 जिलों में से केवल छः में जिला चिकित्सालय हैं। जन स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रदाय में प्रमुख बाधा जनशक्ति की कमी है। स्वास्थ्य सेवायें, विस्तार एवं गुणवत्ता दोनों मामलों में पीछे हैं। राज्य में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 32 ऐलोपैथिक अस्पताल हैं, जबकि यह संख्या *e/; ins'k* के लिये 35 एवं *Hkjr* के लिये 97 है। शिशु मृत्यु दर काफी ऊँची है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भवन, स्टाफ, दवाइयाँ एवं साजो सामान जैसी अधो-संरचना की कमी है। यातायात एवं संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं के अपर्याप्त होने से दूरस्थ क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों तक पहुँच पाना कठिन है।

4.4.6 *XII08 fo-vk* द्वारा प्रदत्त समंकों के अनुसार, *NRrhl x<* के ग्रामीण क्षेत्रों में 22.33% परिवारों को दूर-दूर से पीने का पानी लाना होता है, जबकि *Hkkjr* में यह 19.54% है, *Hkkjr* में 65.82% के विरुद्ध 88.69% घरों में निकासी की सुविधा नहीं है तथा *Hkkjr* के 45.74% के विरुद्ध 94.82% घरों में शौचालय सुविधा नहीं है। यहाँ वि.आ. द्वारा निर्मित इन सुविधाओं से संबंधित *ofprrk dk l pukd* (*Deprivation Index*) 57.4% है, जो 45.74% के *Hkkjr* के सूचनांक से काफी अधिक है। नगरीय क्षेत्रों में 13.67% परिवारों को दूर-दूर से पानी लाना होता है, जबकि *Hkkjr* में यह 9.38% है, *Hkkjr* के 26.28% के विरुद्ध 47.41% घरों में शौचालय नहीं हैं तथा *Hkkjr* के 22.13% के विरुद्ध 37.04% घरों में निकासी सुविधा नहीं है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों के लिये वंचितता सूचकांक 27.95% है, जबकि *l á wkl nsk* के लिये यह 16.79% है। यह सब ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का द्योतक है, जिनमें से अधिकांश का प्रदाय स्थानीय निकायों को करना होता है।

4.4.7 राज्य में, *l kekftd l fo/kkvka* की शोचनीय स्थिति के संदर्भ में आवश्यक हो जाता है, कि सार्वजनिक व्यय एवं आयोजन प्रक्रिया में शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। हमें यह सुनिश्चित करना होगा, कि त्वरित विकास के साथ-साथ मानव विकास पर समुचित ध्यान दिया जाय तथा इस क्षेत्र में विद्यमान बड़ी कमियों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय।

4.5.0 भौतिक अधो-संरचना :

4.5.1 *l Mdj l plj] fl pkbz t9 h HkkSrd v/kk&l jpuk* के मामलों में राज्य बहुत पीछे है। ऊर्जा के मामलों में स्थिति सुखद एवं संतोषजनक है। *e/; insk* राज्य

जिसका, कि **NRRhl x<** 44 वर्षों तक एक भाग रहा है, की भौतिक एवं सामाजिक दोनों अधो-संरचना के अपर्याप्त विकास के कारण ही वृद्धि की उच्च दरें प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रहा है। वृद्धिगत विकास प्रयास को पोषित करने एवं बनाये रखने के लिये राज्य की अधो-संरचना कमजोर है। आंशिक रूप से उसकी स्थल आकृति, तथा आंशिक उसकी बिखरी-बिखरी बसाहट-रचना राज्य की अधो-संरचना की प्रकृति को अधिक पूँजी प्रधान बनाती है।

4.5.2 **xzroa fo-vk** ने **ekuo fodkl l pdkd** एवं **v/kk&l jpkuk l pdkd** संबंधी चुने हुये संकेतकों के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण किया है। **tgk ekuo fodkl l pdkd l kekftd l okvka rd igp dks crkrk g\$ ogha v/kk&l jpkuk l pdkd Hkkfrd l jpkuk ds igp dk ?kkrd g\$ NRRhl x<+rFkk vkl ke] tEew ,oa dk'ehj] >kj [k.M ,oajktLFku** को विकास के निम्न मध्यम वर्ग में रखा गया है। **Hkkfrd v/kk&l jpkuk** के मामलों में इसे निम्न **v/kk&l jpkuk l pdkd** वाले राज्यों के वर्ग में शामिल किया गया है, जिसमें **v: .kkpy ins'k] ef.ki g] e\$ky;] >kj [k.M] fetkje] ukxky\$M] vkl ke] fl fdde] f=i gk] tEew ,oa dk'ehj] fcgkj ,oajktLFku** भी शामिल हैं।

4.5.3 **fl pkbz** सुविधायें अत्यन्त अपर्याप्त हैं। शासकीय एवं निजी सभी क्षेत्रों से कुल सिंचित क्षेत्र 10.46 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 21.70% था, जबकि यही प्रतिशत **e/; ins'k** में 36.70% था। शासकीय स्रोतों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 11.79 लाख हेक्टेयर था, जो मुश्किल से ही राज्य के कुल जोते गये क्षेत्र का 20% था। राज्य की कृषि प्रमुखतः मानसून का जुआ है। कृषि, ऊर्जा उत्पादन, पेय जल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये जल संसाधन अनिवार्य हैं। ये संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, परन्तु उनका दोहन एवं उपयोग नहीं हो रहा है। वर्षा न होने तथा अपर्याप्त सिंचाई सुविधा के कारण राज्य में सूखें की संभावना बनी रहती है। राज्य की स्थल रचना पानी को रोक पाने की दृष्टि से कमजोर है। वर्षा का पानी शीघ्रता से रिस जाता है। राज्य की पठारी भौगोलिक स्थल रचना के

कारण वर्षा के जल की बह जाने की गति अत्यन्त तेज होती है। राज्य की प्रमुख नदी महानदी है, जो वर्षा के अधिकांश पानी को बहा ले जाती है तथा उससे सतत पानी उपलब्ध नहीं होता।

4.5.4 राज्य में जब भी मानसून अपर्याप्त हुआ है, तभी *is ty* की गंभीर कमी रही है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण लोगों का उन सुरक्षित क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ है, जहाँ जल उपलब्ध है।

4.5.5 यद्यपि राज्य में उसके क्षेत्रफल की तुलना में अपर्याप्त रेल नेटवर्क के चलते *l Md ; krk; kr* को राज्य की यातायात व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होना चाहिये। राज्य अर्थव्यवस्था के इस उप-क्षेत्र की प्रगति सड़क नेटवर्क के विस्तार एवं वर्तमान सड़कों के रख-रखाव दोनों दृष्टियों से अत्यन्त धीमी है। प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर कुल सड़कों की लम्बाई केवल 25 कि.मी. है, जबकि यह *nsk* में 75 एवं *e/; ins'k* में 35 है। प्रति 100 वर्ग कि.मी. पर पक्की सड़कों की लम्बाई केवल 17 है, जबकि यह *nsk* में 42 एवं *e/; ins'k* में 19 है।

4.5.6 राज्य में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का विकास तभी हो सकता है, जब वहाँ संपूर्ण देश से वस्तुओं के द्रुत आवागमन के लिये सुविकसित राष्ट्रीय/राज्य हाईवे तथा जिला/ग्राम सड़कें हों। *NRrhl x<* छः राज्यों से घिरा हुआ है। इन सभी राज्यों का यातायात राज्य से होकर जाता है, जिसका यहाँ के सड़क नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव रहता है। राज्य को ऊर्जा एवं उद्योग में अधिक विनियोग हेतु विदेशी एवं घरेलू पूँजी आकर्षित करने के लिये सड़क यातायात के विकास में अधिक प्रगति करनी होगी। निजी एवं विदेशी पूँजी की सहभागिता के साथ इस उप-क्षेत्र में की गयी नीतिगत पहलों के निकट भविष्य में ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, यदि राज्य के विकास के लिये एक सुविचारित एवं समन्वित यातायात नीति अपनाई जाय।

4.5.7 प्रदेश के भीतरी विकास के लिये वायु एवं रेल यातायात महत्वपूर्ण हैं, परन्तु **NRrh x<** में इन दोनों की कमी है। संचार सुविधाओं तथा टेलीफोन एवं डाक सेवाओं की भी राज्य में समान रूप से कमी है।

4.5.8 राज्य में **Åtk dh fLFkr** उत्साहजनक एवं संतोषप्रद है तथा राज्य में ऊर्जा आधिक्य है। वर्ष 1999–2000 में विद्युत का वास्तविक उत्पादन 778.89 करोड़ इकाई था, जिसका केवल 5.5% जल विद्युत था तथा शेष सभी थर्मल ऊर्जा थी। थर्मल इकाइयों का प्लांट लोड फैक्टर 67.96% था। राज्य के पास कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत साधन उपलब्ध है। ऊर्जा आधिक्य के बावजूद प्रति-व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 242 कि.वा. था, जबकि यह **e/; ins'k** में 358 तथा **Hkjr** में 301 था, यह इस बात का द्योतक है, कि राज्य **e/; ins'k** के अन्य प्रक्षेत्रों को ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। **NRrh x<** के निर्माण के समय राज्य के पास पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों का केवल 10% भाग था, जबकि **e/; ins'k** के पास 90%। कमजोर पारेषण एवं वितरण अधो-संरचना के कारण न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, वरन् नगरीय क्षेत्रों में भी कमजोर वोल्टेज एवं प्रायः होने वाली खराबी की गंभीर समस्या थी। राज्य के लगभग 92% ग्राम विद्युतीकृत है, जबकि **e/; ins'k** में यह 97% एवं **l áwł Hkjr** में 85% है। **e/; ins'k** विद्युत मंडल की स्थापित क्षमता का लगभग 68% भाग **NRrh x<** में तथा शेष भाग **e/; ins'k** में स्थित था। अपने वृहद खनिज एवं वन संसाधनों की सहायता से राज्य देश के औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास के मामले में अग्रणी राज्य बन सकता है।

4.5.9 **Hkšrd v/kk&l jpuk** के स्तर में काफी गिरावट हुई है, विशेषतया पाँचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जब दूरगामी नियोजन (Perspective Planning) का महत्व काफी कुछ समाप्त हो गया था तथा उसके स्थान पर लोकलुभावनी नीतियाँ हावी थीं। यह राज्यों के कुल सार्वजनिक व्ययों में भौतिक अधो-संरचना के रख-रखाव एवं विकास पर होने वाले व्यय के घटते अनुपातों से प्रमाणित होता है, विशेषतया

देश में आर्थिक सुधारों के लागू होने के पश्चात् ऊर्जा एवं सिंचाई को दी जाने वाली अत्यधिक सब्सिडी को ध्यान में रखते हुये राज्य को आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के मूल्य निर्धारण में साहसिक कदम उठाने होंगे।

4.6.0 अर्थव्यवस्था का संसाधन आधार :

- 4.6.1 वन, खनिज एवं जल संसाधनों की दृष्टि से राज्य प्राकृतिक साधनों से संपन्न है। विकास की अत्यधिक संभावनायें हैं, परन्तु अपर्याप्त वित्तीय साधनों, मानव संसाधनों की कमी, दूरगामी नियोजन का अभाव, ऐतिहासिक परिदृश्य एवं कमजोर अधो-संरचना के कारण उनका दोहन अपर्याप्त है।
- 4.6.2 राज्य में प्रचुर *ou l i k/ku* हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 44% भाग में वन हैं, जबकि *e/; ins'k* में यह 30% है। आदिवासी जीवन वनों के इर्द-गिर्द केन्द्रित होता है। लगभग 40% वन आर्थिक दृष्टि से काफी मूल्यवान हैं। ये टीक, साल, बाँस, तेन्दूपत्ता इत्यादि हैं, परन्तु राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में ये केवल 2.8% का ही मूल्य वर्द्धन करते हैं। वनों का प्रमुख योगदान है, पर्यावरण पर उनका प्रभाव। यह राज्य के घरेलू उत्पाद एवं राज्य सरकार के राजस्व को योगदान से कहीं अधिक है। राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वाँछित क्षेत्र से अधिक है। एक आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों को ही वन संसाधनों की पहुँच से दूर रखा जाता है, जो आदिवासियों में अत्यधिक असंतोष का कारण है। जनसंख्या को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त प्रदेश के गौण वन उत्पादों से रुपये 500 करोड़ से अधिक आय प्रतिवर्ष उत्पन्न होने की संभावनायें हैं। वर्ष 2004-05 में राज्य कोष को वनों का योगदान रु. 140 करोड़ होने का अनुमान था। केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत उनकी समुचित सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। उनका प्रबंधन वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाता है।

4.6.3 **XI09 fo-vk** ने संपूर्ण देश के वन प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक कार्य योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन की अनुशंसा की थी। बहुत कम राज्यों ने ही ऐसी कार्य योजनाओं को अनुमोदित कराकर उनका क्रियान्वयन प्रारम्भ किया है। उनका कहना है, कि वित्तीय अवरोधों के कारण कार्य योजना के अनुसार वन क्षेत्रों का रख-रखाव एक समस्या हो गयी है। वन राष्ट्रीय संपत्ति हैं तथा उनकी सुरक्षा संपूर्ण देश का उत्तरदायित्व है। **XI09 fo-vk** ने अधिनिर्णय अवधि (2005-10) में राज्यों को ₹ 1000 करोड़ के अनुदान एवं प्रत्येक राज्य को उसके वन क्षेत्र के अनुपात में आबंटन की अनुशंसा की थी। **NRrhl x<+ jkT;** को ₹. 85 करोड़ आबंटित किये गये हैं, जिसका स्थान **v: .kkpy ins'k** एवं **e/; ins'k** के बाद तीसरा है। यह अत्यल्प राशि है। वनों के रख-रखाव के लिये राज्य को अधिकांश राशि स्वयं के साधनों से ही व्यय करनी होती है।

4.6.4 राज्य **[kfu t l k/kuk9** से परिपूर्ण है। यहाँ 11 प्रकार के खनिज पाये जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है – कोयला, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टिन एवं चूना पत्थर। कुल खनिज उत्पाद मूल्य में कोयले का योगदान 82%, लोहे का 13.15%, चूना पत्थर का 4.25%, बॉक्साइट का 0.65% तथा डोलोमाइट का 0.38% है। वर्ष 2000-01 में राज्य में ₹ 3600 करोड़ मूल्य का खनिज उत्पादन हुआ एवं राज्य को ₹ 400 करोड़ का राजस्व मिला, जो बढ़कर 2001-02 में ₹. 455.52 तथा 2003-04 में : - 637 करोड़ हो गया, जो राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 19.74% था। खनिज राजस्व प्रमुखतः केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी दरें एवं समय-समय पर उनमें संशोधन पर निर्भर होता है। राज्य सरकार केन्द्र से रॉयल्टी दरों को अधिक बार संशोधन करने की माँग करती रही है। राज्य के खनिज संसाधन अनेक खनिज-आधारित उद्योगों एवं थर्मल बिजली के विकास का सुदृढ़ आधार हो सकते हैं। राज्य खनिज विकास निगम को राज्य के खनिज विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार कुछ गौण खनिजों के दोहन में कमजोर वर्गों एवं शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता दी गयी है, तथा **i ajk-l lFkkvk** को भी अपने-अपने क्षेत्रों में गौण खनिजों से

राजस्व अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। खनिजों का खनन केन्द्रीय सरकार की नीति से नियन्त्रित होता है। खनिज के दोहन की गति बढ़ाना आवश्यक है। खनिजों के दोहन में राज्य की भूमिका का विस्तार होना चाहिये। एक प्रमुख समस्या अवैधानिक खनन की है, जिसे सख्ती से रोका जाना जरूरी है।

4.6.5 भिलाई स्टील संयंत्र, कोरबा का एल्युमिनियम संयंत्र, अनेक थर्मल ऊर्जा संयंत्र, सीमेंट इकाइयाँ एवं अनेक परिशोधन इकाइयाँ (refractories) राज्य के प्रमुख **[kfut vk/kkjr m/ksx** है।

4.7.0 कृषिगत विकास :

4.7.1 राज्य के आर्थिक विकास के लिये **df"k dk fodkl** अत्यन्त आवश्यक है। केवल कुछ विकसित भू-भागों को छोड़कर कृषि लगातार कम विकसित बनी हुई है। इसमें संपूर्ण देश की तुलना में कार्यकारी जनसंख्या का अधिक अनुपात लगा हुआ है, कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 80% प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 35.5% भाग कृषि के लिये उपलब्ध है। राज्य प्रमुखतः **^kjhQ^** राज्य है, जहाँ प्रधान फसल धान है तथा जिसके अंतर्गत कुल फसल क्षेत्र का 80% भाग है। राज्य में केवल 21% क्षेत्र में ही सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध है तथा शेष कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है।

4.7.2 राज्य की कृषि की एक विशेषता मौसम जनित उच्चावचनों से उत्पन्न उसकी वृद्धि दर की अस्थिरता है। गत शताब्दी के 60 के दशक के मध्य अपनायी गयी नई कृषि रणनीति, जिसने हरित क्रान्ति को जन्म दिया, ने **NRrhl x<** क्षेत्र को दरकिनार रखा। राज्य की फसल गहनता काफी कम है। **e/; ins"k** की 135 एवं **jk"Vh;** **vk/r** 133 के विरुद्ध केवल 121 मुश्किल से ही राज्य के कुल फसल क्षेत्र का 14% भाग ही द्वि-फसली है, जबकि यह म.प्र. में 21% एवं **l áwk/ ns"k** में 25% है। रसायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत कम है, प्रति हेक्टेयर 40 कि.ग्रा., जबकि यह **e/; ins"k** में 48 एवं **Hkkjr** में 90 कि.ग्रा. है। आधुनिक साधनों का उपयोग

प्रमुखतः सिंचित क्षेत्र में बड़े किसानों तक सीमित है। कम उपयोग के अतिरिक्त, उर्वरक उपयोग उसके संतुलित उपयोग मानदण्ड से काफी पीछे है।

- 4.7.3 धान यहाँ की प्रमुख फसल है तथा वर्षा की मात्रा अथवा वितरण किसी में भी होने वाली कमी उसकी उत्पादकता एवं उत्पादन को प्रभावित करती है। धान कुल क्षेत्र के 25 से 30% में उगाया जाता है, भले ही इसे उगाना अनार्थिक हो। वास्तव में राज्य का फसल ढाँचा आदर्श नहीं है। दालों, तिलहन, गन्ना, कपास, मसालें बागवानी, औषधि, पौधे इत्यादि के अंतर्गत और क्षेत्र लाये जाने की आवश्यकता है।
- 4.7.4 वर्ष 1980-81 के बाद से राज्य अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में पूँजी विनियोग में कमी आई है, जो राज्य की घटती विनियोग दर से स्पष्ट होती है। राज्य की औसत जोत का आकार 1.8 हेक्टेयर है, जबकि यह मध्य प्रदेश में 25 है। लगभग 90% कृषक छोटे एवं सीमांत कृषक हैं, जो धान उत्पादन में पराजय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामन्ती बनी हुई है। अधिकांश कृषि 'फसल-बंटारी' के आधार पर की जाती है। राज्य के अनेक भागों में संविदा कृषि हो रही है, जिसके अंतर्गत निजी कृषि-व्यापार कम्पनियाँ छोटे किसानों के उत्पाद तक अपनी पहुँच बनाने का प्रयास कर रही हैं। 'भूमिहीन' श्रमिकों एवं सीमांत कृषकों का पलायन निरंतर हो रहा है, विशेषतया तब जब ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा होता है।
- 4.7.5 धान की उच्च उत्पादन किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तथा उर्वरकों एवं उन्नत तकनीक के अधिक उपयोग के बावजूद उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गयी, भारत की खाद्य असुरक्षा एटलस में *NRrh x<* की पहचान *>kj [k.M] xq jkr*, *oa mMhl k* के साथ *HKjr* के खाद्य असुरक्षित राज्यों की श्रेणी में की गई है। कभी इस क्षेत्र को उसकी धान की किस्मों एवं उन्नत फसल उत्पाद के कारण भारत का 'धान का कटोरा' कहा जाता था। आज के आधुनिकीकरण में एक मात्र ध्यान नई उच्च उत्पादन किस्मों पर दिया गया है तथा स्वदेशी विविधता की अवहेलना की गई है। क्षेत्र की कुछ स्वदेशी धान की किस्में उच्च उत्पादकता वाली

एवं कीट-रोधी हैं, परन्तु प्रतीत होता है, कि राज्य में धान की किस्मों के इस भण्डार को भुला दिया गया है तथा नई किस्मों के विकास एवं अधिक उत्पादन पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है। विपरीत अवस्थाओं में भी, जब आधुनिक किस्में पूरी तरह फेल हो जाती हैं, पारम्परिक किस्में न्यून से मध्यम उपज दे देती हैं।¹

4.7.6 राज्य में संगठित विपणन संरचना का अभाव है। बिचौलियों का हिस्सा बहुत अधिक है। कृषक का शोषण होता है तथा उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता। कृषि बाजारों में जारी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिये आवश्यक है, कि राज्य में सहकारी एवं नियन्त्रित विपणन प्रणाली विकसित करने के प्रयास किये जाये।

4.7.7 राज्यों के लिये फसल ढांचे का विविधीकरण अधिक सिंचाई सुविधाओं, जल संग्रहण क्षेत्रों के विकास का प्रबल प्रयास, फसल किस्मों का उचित एवं संतुलित चयन, छोटे एवं सीमांत कृषकों को अधिक सहायता, भूमिहीन श्रमिकों के लिये रोजगार योजनाओं, विस्तार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, इस क्षेत्र में अधिक मूल्य संवर्धन, ग्रामीण अधो-संरचना में अधिक विनियोग, संगठित विपणन प्रणाली की स्थापना, अधिक संस्थागत वित्त, विपणन एवं भण्डारण सुविधाओं का विकास तथा विकेन्द्रित नियोजन की संपुष्टि की आवश्यकता है। सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है, कि कृषि विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार निर्माण तथा गरीबी हटाओं कार्यक्रमों के बीच विकेन्द्रित आधार पर समन्वय स्थापित हो।

4.8.0 औद्योगिक विकास :

4.8.1 इस तथ्य के बावजूद, कि राज्य में ऐसे प्रचुर वन एवं खनिज साधन उपलब्ध हैं, जो अनेक कृषि आधारित, खनिज आधारित एवं वन आधारित उद्योगों एवं थर्मल ऊर्जा का संपुष्टि आधार हो सकते हैं, राज्य की गिनती *11th* के कम औद्योगिक विकास वाले राज्यों में की जाती है। उसकी देश के केन्द्र में स्थिति, उसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

1. मीना मेंनन-धान के कटोरे में दरारें, इ.पी.डब्ल्यू साप्ताहिकी - 9 जून 2001, पृ. 2028-30

4.8.2 राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें निर्माण उद्योग एवं ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण शामिल हैं, का अंश लगभग 25 अथवा 26% है। पंजीयत एवं गैर पंजीयत दोनों को शामिल करते हुये, निर्माणी क्षेत्र का राज्य के सघ.उ. को योगदान लगभग 17% है, जो *e/; ins'k* से अधिक है तथा जो *e/; ins'k* की तुलना में इसके औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास के उच्च स्तर का द्योतक है, फिर भी *NRrhI x<* के औद्योगिक विकास का स्तर इसकी संभावनाओं की तुलना में काफी कम है। संभावनाओं के रहते हुये भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास धीमा रहा है। दो बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों – *flkykbZ LVhy Iyka/* एवं *Hkkjr , Y; wlfu; e dEi uh* (जिसका बाद में निजीकरण हो गया) तथा स्थानीय तौर पर उपलब्ध खनिज संसधानों पर आधारित कुछ सीमेंट एवं स्पंज आयरन इकाइयों के अतिरिक्त राज्य में और कोई प्रमुख औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं। औद्योगिक विकास का फैलाव दुर्ग एवं रायपुर जिलों में रेल्वे लाईन के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित है। अधिकांश जिलों में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक अधो-संरचना नहीं है।

4.8.3 राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 65% भाग उद्योगों द्वारा, 12.3% सिंचाई द्वारा तथा 18% घरेलू उपभोग के रूप में उपयोग किया जाता है। राज्य में, वर्ष 1998 में, पंजीकृत कारखानों की संख्या 2553 थी, जो बढ़कर 2001 में 2706 हो गई, जिनमें औसतन प्रतिदिन 13000 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। वर्तमान में राज्य में केवल चार प्रमुख विकास केन्द्र हैं, जो *jk; ig] nqZ , oafcykl ig* जिलों में स्थित हैं। विकास केन्द्रों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लालफीताशाही एवं प्रक्रियात्मक रूकावटों को समाप्त करना, निजी सहभागिता के साथ पर्याप्त अधो-संरचना का निर्माण, छोटे पैमाने की इकाइयों का संवर्धन तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा जैसे उद्देश्यों के साथ राज्य की वर्ष 2004-09 की औद्योगिक नीति काफी महत्वाकांक्षी प्रतीत होती है। राज्य में अनेक परम्परागत ग्रामीण उद्योग हैं। विशेषतया रेशम, हाथकरघा तथा खादी एवं ग्राम उद्योग। राज्य को सुनिश्चित करना होगा, कि अधिक उदार वातावरण में ये उद्योग कहीं प्रतिस्पर्धा की मार से

समाप्त न हो जायें। इनमें रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए, इनका संरक्षण एवं युक्तयुक्तीकरण कर इन्हें जारी रखना होगा।

4.8.4 इस राज्य की विशेषता, इसके *l d k/ku&vkk/kfjr m / kska* जैसे लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम एवं ऊर्जा में है। किसी उल्लेखनीय सीमा तक पहुँचने के लिये इसके उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों का अभी विकास किया जाना है। राज्य की औद्योगिक संरचना एकांगी है तथा उससे राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये अंतर्क्षेत्रीय संबंध तथा केन्द्रीकरण की मितव्ययितायें सुनिश्चित नहीं होती। 'निर्यात-आधारित' उद्योगों का गुणक प्रभाव कमजोर होता है, इसलिये उन्होंने किसी बड़े पैमाने पर राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया है।

4.8.5 अब विनियोजन संबंधी निर्णय राष्ट्रीय नियोजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से संचालित नहीं होते। अब विनियोजन शुद्ध आर्थिक उद्देश्यों से किया जाता है, अब इकाइयों की क्षमतायें एवं रणनीतियाँ, प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियाँ तथा विभिन्न स्थानों का विनियोजन वातावरण निर्णायक बिंदु हो गये हैं। विनियोजन वातावरण से हमारा आशय, उस संस्थागत नियामक एवं नीति वातावरण से है, जिनमें इकाइयों को कार्य करना होता है। *kkjr* के विभिन्न राज्यों में यह वातावरण काफी भिन्न हो सकता है तथा यह भिन्नता संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, नियमन के प्रति दृष्टिकोण, अधो-संरचना की व्यवस्था तथा वित्त एवं श्रम बाजार के क्रियाकलापों के मामलों में राज्यों के बीच अंतर पर निर्भर है। इन वर्णित वातावरणीय परिस्थितियों के अभाव में अनेक समझौता-पत्र एवं आशय-पत्र क्रियान्वित नहीं हो पाते। पिछड़े राज्यों को अपने आर्थिक सुधारों के द्वारा अपना विनियोजन वातावरण अधिक व्यापार-मित्र बनाना होगा, परन्तु बाजार मित्र वातावरण का यह अर्थ नहीं है, कि सरकार की नियामक व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी जाय। बाजार की असफलताओं पर ध्यान देने एवं सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिये सरकारी नियमन आवश्यक हैं, परन्तु सरकार की नीतियाँ एवं प्रक्रियायें पारदर्शी

हों तथा उपक्रमों के लिये विनियोग एवं विस्तार संबंधी प्रेरकों को न बिगाड़े। उदारीकरण के क्षेत्र में, सरकार को लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामाजिक एवं आर्थिक अधो-संरचना के विकास में विनियोजन करने तथा वित्त एवं श्रम बाजार के शांत रूप से कार्य करना, सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।¹

4.8.6 राज्य में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं। औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार अनेक छूटें एवं सहायता दे रही है। परन्तु जब तक बाजार-मित्र विनियोजन वातावरण निर्मित नहीं होता, ये छूटें एवं सहायता राज्य में उद्योगों को आकर्षित नहीं कर सकेंगी।

4.9.0 बैंकिंग विकास :

4.9.1 कृषि, उद्योग, एवं व्यापारिक विकास के लिये साख एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग का विकास उन गैर संस्थागत एजेसियों को हटाने के लिये भी आवश्यक है, जो विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वर्तमान राज्य में राज्य सहकारी बैंक के अतिरिक्त 29 व्यापारिक बैंक (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की), 55 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 6 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कार्यरत हैं। जून 2004 में राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की 583 शाखायें थी, जिनकी कुल जमायें रु 11,610 करोड़ एवं कुल साख रु. 4,511 करोड़ थी। इस प्रकार इनका साख जमा अनुपात 38.85% था, जो *e/; ins'k* के 47.14% एवं *egkjk"V"* के 70% की तुलना में काफी कम है। राज्य की कुल बैंक साख में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का अंश 38.90% था, जबकि यह *e/; ins'k* में 53.3% था। प्रति शाखा सेवित औसत जनसंख्या 15,838 थी। यह

1. Veermali and Golder - Manufacturing Productivity in Indian States- Doesa invesament climate matter ? Economic and Political weekly, June 11. 2005, p. 2413

देखते हुये, कि **NRrh x<** में प्रति शाखा औसत जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में और अधिक बैंक शाखाओं के लिये अवसर हैं।

4.9.2 उपर्युक्त समंकों, जो केवल सार्वजनिक बैंकों का कार्य निष्पादन बताते हैं, की तुलना में 31 मार्च 2004 की स्थिति में राज्य की समस्त बैंकों की समग्र जमायें, अग्रिम तथा साख जमा अनुपात अधिक व्यापक स्थिति प्रस्तुत करता हैं। **l kj.kh dz 4-2 jkT; dh c&ks ds dk; / fu"iknu dks iLr r djrh g**

4.9.3 यद्यपि साख जमा अनुपात 60% के लक्ष्य के नज़दीक है, परन्तु अन्य राशियाँ लक्ष्य के पीछे हैं। यह शोचनीय है, कि कृषि एवं कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों में गिरावट हुयी है, कृषि में यह 2002 में 24.01% से घटकर 2003 में 17.1% तथा 2004 में 13.88% एवं कमजोर वर्गों को 2002 में 14.05% से 2003 में 10.15% एवं 2004 में 9.53% रह गये। साख के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जानी चाहिये। वर्तमान में **l kj.kh Ø- 4-2** के अनुसार साख जमा अनुपात में वृद्धि होकर वह 60% के लक्ष्य के समीप है, परन्तु कृषि एवं कमजोर वर्गों के अग्रिम घटे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है।

4.10.0 राज्य अर्थव्यवस्था का विकास निष्पादन :

4.10.1 अध्याय के पिछले परिच्छेदों में राज्य की अर्थव्यवस्था की त्वरित समीक्षा करते हुए, हमने उन कारकों को भी चिन्हित किया है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास मार्ग में अवरोध बने हुये हैं। हमने इन कारकों को विकास अवरोधक कारक की संज्ञा दी है। इस समीक्षा से विभिन्न क्षेत्रों के विकास में बदलती प्राथमिकतायें भी स्पष्ट हुई हैं। हमने उन कारकों की भी पहचान की है, जो अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को गति दे सकते हैं। इन कारकों को विकास गतिवर्धक कारक कहा जा सकता है। जब तक विकास गतिवर्धक कारकों की गति, विकास अवरोधक कारकों की गति से तेज नहीं होती, राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास, उसकी संपूर्ण संभावनाओं के अनुरूप नहीं हो सकता। नियोजन प्रक्रिया एवं सरकारी नीतियों का प्रमुख उद्देश्य विकास गतिवर्धक कारकों की गति को बढ़ाकर तथा

विकास अवरोधक कारकों की पकड़ ढीली करके अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर ले जाना होना चाहिये।

4.10.2 इन दोनों कारकों का प्रभाव राज्य अर्थव्यवस्था के विकास निष्पादन पर पड़ता है, जो अंततः एक महत्वपूर्ण वृहतचर राज्य के घरेलू उत्पाद के रूप में परिलक्षित होता है। यह एक वर्ष में सभी सृजित आय अथवा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के द्वारा किये गये मूल्य संवर्द्धन का महायोग होता है। यह सकल होता है, जब इसमें से ह्रास न घटाया गया हो। यह 'घरेलू' है, क्योंकि इसमें राज्य की सीमाओं में सृजित आय ही शामिल होती है तथा राज्य के बाहर से आने एवं जाने वाले मूल्य की गणना नहीं की जाती।

4.10.3 *e/; ins'k* जिसका, कि *NRrhl x<* क्षेत्र 44 वर्षों तक एक भाग रहा है, में विद्यमान अनेक भौतिक, सामाजिक, संस्थागत, वित्तीय एवं प्रशासकीय अवरोधों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी रही है। वृद्धिकारक शक्तियाँ इतनी विकसित नहीं हो पायी हैं, कि राज्य विभिन्न दिशाओं में तीव्र प्रगति कर सके। विकास के अधिकांश संकेतांकों के मामले में राज्य देश की विकास सीढ़ी के निम्नतम पायदान पर बना हुआ है। *Hkkjr* के मध्यम आय वाले राज्यों के वर्ग में शामिल होने के लिये राज्य को काफी बड़े अंतराल की पूर्ति करनी होगी।

4.10.4 वर्ष 2005-06 का *NRrhl x<* का आर्थिक सर्वेक्षण, *jkT; ds 'kq ?kjsyw* उत्पाद वर्तमान एवं स्थिर (1993-94) दोनों मूल्यों पर संबंधी समंक अधिक बाद के वर्षों के लिये उपलब्ध कराता है।

*rgyukRed v/; ; u dh n'V l s geus Hkkjr l jdkj }kjk
i xdkf'kr o"K 2004&05 ds vkfFkd l o'k.k ds l eadka dks l kj.kh Ø-
4-3* में प्रस्तुत किया है।

4.10.5 वर्ष 1993-94 में वर्तमान मूल्यों पर *NRrhl x<* की *"kq jkT; ?kjsyw mRi kn* *¼'kqjk-?k-m-½ e/; ins'k* की 35.80% था, जो 2000-01 में घटकर 32.00% परन्तु 2001-02 एवं 2002-03 में बढ़कर क्रमशः 33.99% एवं 35.15% हो गया। गिरावट

का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र की गिरावट बताया गया है। वर्ष 1993-94 में **NRrhl x<** का प्रति व्यक्ति **"kgjk?km- e/; ins'k** का 99.31% था, जो 2000-01 में घटकर 92.69% रह गया, परन्तु 2002-03 में बढ़कर 103.97% हो गया। यह दर्शाता है, कि वर्ष 2002-03 में **NRrhl x<+ jkT;** की प्रति-व्यक्ति आय **e/; ins'k** से अधिक थी।

4.10.6 जिन 32 राज्यों के समंक आर्थिक सर्वेक्षण (2004-05) में उपलब्ध हैं, उनमें वर्ष 2001-02 में **NRrhl x<** का स्थान 25वाँ था, जो सात राज्यों – **vkl ke] fcgkj] >kj [k.M] e9kky; ; mMhl kj mRrj ins'k , oaef.kij** से ऊँचा था।

4.10.7 **xIIOa fo-vk us Hkh 28 jkT; ka ds I -jk?k-m- I adkh I ad fn; s g9 geus NRrhl x<} e/; ins'k , oa Hkjr I adkh I ad fy; s g9 ftUga I kj.kh dz 4-4** में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी से ज्ञात होता है, कि वर्ष 2000-01 में **NRrhl x<** वर्तमान मूल्यों पर प्रति-व्यक्ति **I -jk?k-m-** के मामले में मध्य प्रदेश से आगे निकल गया है। राज्य की औसत प्रति-व्यक्ति आय **e/; ins'k** की प्रति-व्यक्ति आय से अधिक थी। प्रतिवेदन में जिन 28 राज्यों के समंक उपलब्ध हैं, उनमें **NRrhl x<** का स्थान 22वाँ तथा **e/; ins'k** का 23वाँ था, परन्तु "कुल राज्यों" के औसत की तुलना में राज्य काफी पीछे है।

4.10.8 उपर्युक्त प्रस्तुत तथ्य प्रदर्शित करते हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है। इसका आंशिक कारण यह हो सकता है, कि अपनी स्थापना की प्रारम्भिक अवधि में राज्य को अपने प्रयास एवं अपने संसाधन सरकार को नये स्थान पर ले जाने एवं व्यवस्थित होने पर केन्द्रित करने पड़े होंगे। इसके अतिरिक्त स्थापना के बाद की पाँच वर्ष की अवधि, जिसमें अनेक प्रारम्भिक कठिनाईयाँ भी थी, विकास निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से अत्यल्प अवधि है।

4.10.9 अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर एवं भौतिक तथा सामाजिक अधो-संरचना के निम्न स्तर के कारण राज्य के लगभग 42.60% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य में गरीबी में कमी करने के लिये, उसे वर्तमान से अधिक दर से वृद्धि करनी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा, कि विकास के लाभ, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जो राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 43.37% हैं, पहुँचे। बाज़ार स्वयमेव गरीबी की समस्या का समाधान अपने खिलाड़ियों की असमान शक्तियों के कारण नहीं कर सकता। राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में बाज़ार के क्रियाकलापों पर निगाह रखने एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करने के लिये नियामक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। यह आवश्यक होगा, कि नियामक व्यवस्था गरीबों को सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित करने में प्रभावी एवं शक्ति संपन्न हो, विशेषकर शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में।

4.11.0 राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन :

4.11.1 आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में *I jpuRed ifjorU* होते हैं, जो राज्य के घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक योगदान में होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होते हैं। *I kj.kh dz 4-5 में jkT; vFkD; oLFkk ea nh?kdky ea gkus okys , I s i fjorUka dks* प्रस्तुत किया गया है।

4.11.2 *i kFkfed {ks-}* जिसमें प्रमुखतः कृषि शामिल है, का अंश वर्ष 1993-94 के 40.33% से घटकर 1999-2000 में 36.39% तथा 2002-03 में 33.27% रह गया। कृषि क्षेत्र का खराब निष्पादन एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्षिक अंश में वृद्धि, इस गिरावट के मुख्य कारण हैं। राज्य के कुल रोजगार में कृषि का योगदान *I -jk-?k-m-* में उसके योगदान से अधिक है, जो प्रति-व्यक्ति कम उत्पादकता का द्योतक है। राज्य के *I -jk-?k-m-* में *f}rh; d {ks-* के योगदान का प्रतिशत *e/; ins'k* से अधिक है, जो *NRrhl x<+ jkT;* के उच्च औद्योगिक एवं ऊर्जा

उत्पादन का द्योतक है, परन्तु नये राज्य की स्थापना के बाद से इस प्रतिशत में गिरावट हो रही है। वर्ष 1999-2000 में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 28.15% था, परन्तु 2002-03 में यह बढ़कर 29.31% हो गया। राज्य में **l ok {ks=** का योगदान 1993-94 के 29.44% से बढ़कर 1999-00 में 35.46% तथा 2002-03 में 37.41% हो गया। **jkT; vFkD; oLFkk dk doy ; gh {ks= g\$ ftl ea fujaej of) gplz g\$ rFkk ftl dk jkT; dh l-jk-?k-m- ea l okf/kd ifr'kr ; kxnku g\$ Hkkjrh;** अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों की तुलना में **NRrhl x<** की अर्थव्यवस्था के ऐसे परिवर्तन धीमें हैं। विशेष तौर से द्वितीयक क्षेत्र के राज्य **l-jk-?k-m-** के योगदान में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, जो राज्य के धीमे औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास का द्योतक है।

4.11.3 कुल मिलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था धीमी गति से वृद्धिमान है तथा संरचनात्मक परिवर्तन भी असंतुलित हैं। परिणाम है, कि राज्य की रोजगार संरचना में अल्प परिवर्तन ही हुआ है। राज्य की 80% जनसंख्या, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं जहाँ उत्पादकता अत्यन्त कम एवं गरीबी व्यापक है।

4.12.0 उपसंहार :

4.12.1 राज्य धीमी गति से प्रगति कर रहा है, इसकी वर्तमान वृद्धि दर से राज्य की गरीबी में कोई विशेष सुधार नहीं हो सकेगा। प्राकृतिक साधनों के मामले में राज्य धनी है। काफी सीमा तक इसे इसकी गरीबी विरासत में मिली है। अब इसे सदियों की दूरी दशकों में तथा दशकों की दूरी वर्षों में तय करना है। राज्य का छोटा आकार, अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं जातिगत पहचान तथा वृहद एवं विविध प्राकृतिक साधनों के साथ तीव्र वृद्धि के पर्याप्त अवसर उपस्थित कराता है। आवश्यक है, दूरगामी दृष्टिकोण एवं विकास की प्रतिबद्धता की। राज्य को

वर्तमान से कहीं अधिक दर से विकास करना होगा। *fofHkUu {ks=ka ea vko'; d fofu; ks ds fy; s bl s vf/kd foRrh; I k/kuka dk I 'tu djuk gksxA jkT; dh jkt dks'kh; uhfr dks , d k cukuk gksxk] fd ml I s fofu; kstu grq jktLo vfrj d fufe'r gksA ?kjsyw , oa fons'kh nkuka I ksrka I s vf/kd I d k/ku tq/k dj vFkD; oLFkk ea fofu; ks c<kuk gksxA*

4.12.2 *df"k ekuo I d k/ku fodkl , oaHkkrd v/k&I jpuk* वे प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन पर प्रयासों को केन्द्रित करना होगा। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप देश में निर्मित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को ध्यान में रखते हुये, राज्य सरकार को अपनी कृषि उद्योग एवं अधो-संरचना नीतियों को नया स्वरूप देना होगा। कार्यो एवं सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से स्थानिक नियोजन के माध्यम से सामाजिक एवं भौतिक अधो-संरचना के अंतरालों एवं कमियों की पहचान कर, उन्हें दूर करना होगा।

4.12.3 *jkT; I jdkj dks iæ[k : i I s iDr d] I qedrkZ , oa fu; ked dh Hkfedk fuHkkuh gksxA ml s , d h ; kstuk; a cukuh gksxh] ftuea futh {ks= dh Hkh Hkxhnhkj gksA fofHkUu {ks=ka ea fufe'r fu; ked rU= dkj jkT; ea fofHkUu f[kyfm; ka dks I ery [ky eñku miyG/k djkus ds mnns'; I s Loræ] békunkj] i Hkoh , oa ikjn'kh' cukuk gksxA os jkT; gh vf/kd rhoz fodkl dj I dks rFkk xjhch dks ?kV I dks tks ddkyrk , oa i Hkoh fu; ked rU= ds I kFk cgrj fofu; kstu okrkoj.k dks c<kok ns I dks rFkk tks ^ekuoh; pgjs^ ds I kFk vkfFkd I qkkj ylxw dj I dksA*

सारणी क. 4.1

NRrhl x<} e/; i ns'k , oaHkkr ea I k{kjrk nja
1991 , oa2001½

(% ea)

Ø-	jkT; @ns'k	0; fDr I k{kjrk nj		i q "k I k{kjrk nj		efgyk I k{kjrk nj	
		1991	2001	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	NRrhl x<+	42.9	65.18	58.10	77.86	27.50	54.4
2.	e/; ins'k	44.7	64.11	58.5	78.7	29.4	50.3
3.	Hkkjr	52.2	67.38	64.1	78.85	39.2	54.16

सारणी क्र. 4.2
 jkT; ea cfdka dk dk; Z fu"i knu
 1/2002 I s 2004 1/2

Ø	fooj.k	ekud Lrj Benchmark %	31-3-02 dh fLFkfr ea	31-3-03 dh fLFkfr ea	31-3-04 dh fLFkfr ea
1	2	3	4	5	6
1	साख जमा अनुपात	60%	51.85	54.4	58.89
2	कुल साख में प्राथमिकता क्षेत्रों का प्रतिशत	40	55.59	38.18	32.69
3	कुल साख में कृषि साख का %	18	24.01	17.1	13.88
4	कमजोर वर्गों को अग्रिम	10	14.05	10.15	9.53

(स्रोत - छत्तीसगढ़ की वार्षिक योजना- 2005-06, पृ. 13)

सारणी क्र. 4.3
 e/; ins'k , oa NRrhl x<+ jkT; ea "kjk?k-m- dh ryukRed fLFkfr
 1/1993&94 , oa 2000&01 I s 2002&03 1/2

1/4 dj kM/ka ea 1/2

Ø-	fooj.k	1993-94	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6

1	चालू मूल्यों पर जु.रा.घ.उ. 1. छत्तीसगढ़	12163	20539	24980	25094
	2. मध्यप्रदेश	33937	64115	73480	71384
2	छत्तीसगढ़ का जु.रा.घ.उ. मध्यप्रदेश के % के रूप में	35.80	32.0	33.99	35.15
	प्रति-व्यक्ति जु.रा.घ.उ. चालू मूल्यों पर (रु.)				
	1. छत्तीसगढ़	6539	9922	11952	11893
	2. मध्यप्रदेश	6584	10704	12027	11438
	छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति जु.रा.घ.उ. मध्य प्रदेश के प्रतिशत के रूप में	99.31	92.69	99.37	103.97

सारणी क्र. 4.4
 1999-00 से 2001-02 तक
 प्रतिव्यक्ति जु.रा.घ.उ. का

विवरण

क्र.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	वर्धन
1	2	3	4	5	6
1	छत्तीसगढ़	13346	12867	14918	13710
2.	मध्यप्रदेश	13489	12572	13960	13340
3	सभी राज्य	16184	16858	17892	16978

सारणी क्र. 4.5
 नरहल ख<+jKT; dh vfk0; oLFk ea l jpuKRed ifjorU
 1/1993&94 l s 2002&03½

(% ea)

Ø-	fks=	fofHKU fks=ka dk "kajk-?k-m- dks ; kxku& orZku eW ; ka i j									
		1993 &94	94&9 5	95&96	96&9 7	97&98	98&9 9	99&2 000	2000& 01	01&0 2	02&03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक	40.33	40.31	38.25	37.96	33.46	34.66	36.39	34.53	39.10	33.27
2	द्वितीयक	30.23	29.35	29.96	29.59	35.65	33.13	28.15	26.33	22.80	29.31
3	तृतीयक	29.44	30.34	31.79	32.45	30.90	32.21	35.46	39.14	38.11	37.41

(स्रोत- छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण (2004-05) एवं वार्षिक योजना, 2005-06)